



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125224

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 2349 वर्ष 2026

रोमेन्द्र मेहता

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: आदित्य गुप्ता, संजय श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: अमृता राय मिश्रा, आलोक रंजन मिश्रा, जी.ए.

निर्णय आरक्षित दिनांक : 07.05.2026

निर्णय प्रदत्त दिनांक : 04.06.2026

न्यायालय संख्या - 34

माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश

1. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विनय सरन, जिन्हें अधिवक्ता श्री आदित्य गुप्ता एवं श्री संजय श्रीवास्तव द्वारा सहयोग दिया गया; विपक्षी संख्या- 2 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, जिन्हें विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक रंजन मिश्रा एवं सुश्री अमृता राय मिश्रा द्वारा सहयोग दिया गया; तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत यह आवेदन विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 1, कानपुर नगर द्वारा पारित समन आदेश दिनांक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



22.08.2024 और विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 18, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.2025 को चुनौती देता है।

3. विवाद विपक्षी संख्या- 2 द्वारा दर्ज कराई गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट से उत्पन्न होता है, जो थाना कोतवाली, जिला ईस्ट कमिश्नरेट, कानपुर नगर में आवेदक के विरुद्ध वाद अपराध संख्या- 200 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 198, 199, 205 और 420 आईपीसी के रूप में पंजीकृत की गयी जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2020 में, आवेदक ने जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के कार्यालय में चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था। आगे यह आरोप लगाया गया है कि उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, उसने जांच अधिकारी को धोखा देकर एक झूठी रिपोर्ट तैयार करवाई और थाना स्वरूप नगर, जिला कानपुर नगर में अंतर्गत धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120बी आईपीसी के तहत वाद अपराध संख्या- 128 वर्ष 2018 के रूप में दर्ज प्राथमिकी के तथ्य को छुपाया। यह भी आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने जानबूझकर इस तथ्य को छिपाया कि उसे उस मामले में समन किया गया था और इस प्रकार वह चरित्र प्रमाण पत्र संख्या- 249/ए.आर.ए.-1/2020-21 दिनांक 29.06.2021 प्राप्त करने में सफल रहा।

4. विवेचक ने विपक्षी संख्या- 2 और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए तथा दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए। विवेचना के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर उसने पाया कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। तत्पश्चात, दिनांक 17.03.2024 को न्यायालय में धारा 173(2) दं.प्र.सं. के तहत एक अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई।

5. विपक्षी संख्या- 2 ने विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-I, कानपुर नगर के न्यायालय के समक्ष एक विरोध याचिका दायर की। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और आदेश दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से आवेदक के विरुद्ध धारा 198, 199 और 420 आईपीसी के तहत संज्ञान लिया।

6. आवेदक ने आक्षेपित समन आदेश के विरुद्ध आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 593 वर्ष 2024 दायर की। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 18, कानपुर नगर ने आदेश दिनांक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28.07.2025 द्वारा उक्त आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। आक्षेपित आदेशों से व्यथित होकर वर्तमान आवेदन दायर किया गया है।

7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित आदेशों को चुनौती देते हैं:

(i) समन आदेश दिनांक 22.08.2024 गंभीर कानूनी त्रुटियों से ग्रस्त है, क्योंकि आवेदक को समन करने का औचित्य साबित करने के लिए कोई सामग्री मौजूद नहीं थी। विपक्षी संख्या- 2 ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाया कि उसने 21.04.2023 को जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के समक्ष एक आवेदन/परिवाद भी दर्ज कराई थी, जिसमें उपरोक्त चरित्र प्रमाण पत्र को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। संबंधित प्राधिकारी ने इसकी विस्तृत और गहन जांच की। इसके बाद, उक्त रिपोर्ट के आधार पर, जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिनांक 12.09.2023 द्वारा उक्त परिवाद को निराधार और बिना किसी आधार के खारिज कर दिया।

(ii) वह आगे कहते हैं कि थाना कोतवाली, जिला ईस्ट कमिश्नरेट, कानपुर नगर में धारा 198, 199, 205 और 420 आईपीसी के तहत वाद अपराध संख्या- 200 वर्ष 2023 के दर्ज होने के बाद, विवेचक ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए और पाया कि आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है तथा अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। तत्पश्चात, विपक्षी संख्या- 2 ने एक विरोध याचिका दायर की, और विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और आवेदक को धारा 198, 199 और 420 आईपीसी के तहत समन कर लिया।

(iii) विद्वान मजिस्ट्रेट इस तथ्य को समझने में विफल रहे कि धारा 198, 199 और 420 आईपीसी के तहत अपराध को गठित करने के लिए कोई भी तत्व मौजूद नहीं हैं, क्योंकि आवेदक की ओर से ऐसा कोई आशय या आपराधिक दुराशय विद्यमान नहीं था।

(iv) वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि धारा 195(1)(ख)(i) दं.प्र.सं. के अनुसार, न्यायालय या न्यायालय के ऐसे अधिकारी जिसे वह न्यायालय लिखित रूप में अधिकृत करे, की लिखित परिवाद के बिना कोई भी न्यायालय धारा 199 आईपीसी का संज्ञान नहीं ले सकता है। धारा 195 दं.प्र.सं. के प्रावधान अनिवार्य हैं, और उनका अनुपालन न करने से अभियोजन और अन्य सभी आनुषंगिक आदेश दूषित हो जाएंगे। धारा 198 और 199 आईपीसी गैर-संज्ञेय अपराध हैं;

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसलिए, वह आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा विद्वान मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और आवेदक को समन किया, न केवल अवैध है बल्कि कानून का घोर दुरुपयोग है।

(v) अभियोजन पक्ष के मामले को सर्वोपरि मानते हुए भी, लेकिन एक शब्द भी स्वीकार न करते हुए, किसी भी तरह से आवेदक के विरुद्ध धारा 420 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। परिवादी ने न तो आवेदक द्वारा किए गए किसी मिथ्या व्यपदेशन पर कोई कृत्य किया और न ही अपनी किसी संपत्ति को सौंपा, और न ही उसने ऐसा कुछ करने से परहेज किया जो वह अन्यथा करता या न करता; इसलिए, धारा 420 आईपीसी के तहत कोई अपराध बिल्कुल नहीं बनता है।

(vi) विपक्षी संख्या- 2 के कहने पर आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना दुर्भावनापूर्ण है और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा आक्षेपित समन आदेश को निरस्त करने के लिए धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अपने अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाना न्यायसंगत है। इस संबंध में **हरियाणा राज्य व अन्य बनाम भजन लाल व अन्य, ए.आई.आर. 1992 एससी 604 और प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2025) एससीसी ऑनलाइन 1947** पर अवलम्ब लिया गया है।

8. इसके विपरीत, विपक्षी संख्या- 2 के विद्वान अधिवक्ता समन आदेश का समर्थन करते हैं और मूल रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:

(i) समन आदेश का एक विस्तृत या व्यापक आदेश होना आवश्यक नहीं है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भूषण कुमार एवं अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली), (2012) 5 एससीसी 422** के मामले में माना है। यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को समन करते समय, मजिस्ट्रेट को केवल यह राय बनानी होती है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं और विस्तृत कारण दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। आक्षेपित आदेश, किसी भी स्थिति में, एक विस्तृत और सकारण आदेश है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों पर विचार किया है और पाया है कि आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है।

(ii) वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि एक बार जब मजिस्ट्रेट ने अपनी इस वैधानिक शक्ति का प्रयोग कर लिया और प्रथम दृष्ट्या विचार दर्ज कर लिया, तो आवेदक धारा 528

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बी.एन.एस.एस. के तहत आवेदन में तथ्यात्मक पहलुओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग नहीं कर सकता।

(iii) प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज होने के चरण में, वाद के अधिकार का प्रश्न पूरी तरह से अप्रासंगिक है। परिवादी को अपराध का पीड़ित होना आवश्यक नहीं है।

(iv) धोखाधड़ी का अपराध उसी क्षण पूर्ण हो जाता है जब प्रेरित व्यक्ति के साथ छल किया जाता है, चाहे मामला कानून प्रवर्तन एजेंसी को कोई भी सूचित करे।

(v) प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम दृष्ट्या, एक संज्ञेय अपराध कारित होना प्रकट करती है। धारा 415 आईपीसी धोखाधड़ी को परिभाषित करती है और दो चरणों के माध्यम से संचालित होती है। दूसरा चरण तब आकर्षित होता है जहाँ एक व्यक्ति, दूसरे को धोखा देकर, जानबूझकर उस व्यक्ति को कुछ ऐसा करने या न करने के लिए प्रेरित करता है जो वह अन्यथा नहीं करता यदि उसे इस प्रकार धोखा न दिया गया होता, और ऐसा कृत्य या लोप उस व्यक्ति को शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति में क्षति या नुकसान पहुँचाता है या पहुँचाना संभावित है। तथ्यों के आधार पर, आवेदक ने अपने आपराधिक इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को सक्रिय रूप से दबाकर और जानबूझकर छुपाकर सक्षम सार्वजनिक प्राधिकारी को धोखा दिया और जानबूझकर उसे अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रेरित किया। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि यदि आवेदक द्वारा सही और सटीक तथ्यों का खुलासा किया गया होता, तो सार्वजनिक प्राधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए उक्त प्रमाण पत्र जारी नहीं करता।

(vi) उन महत्वपूर्ण तथ्यों को सक्रिय रूप से छुपाना जिन्हें प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति कानूनी रूप से बाध्य है, धारा 415 आईपीसी के स्पष्टीकरण के तहत छल की श्रेणी में आता है। छल, बेईमानी से प्रलोभन, और छले गए प्राधिकारी के परिणामी कृत्य के आवश्यक तत्व अभिलेख से प्रथम दृष्ट्या स्थापित होते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र धारा 415 आईपीसी के अर्थ के अंतर्गत संपत्ति की श्रेणी में आता है।

(vii) प्राथमिकी और अब तक एकत्र की गई विवेचना सामग्री प्रथम दृष्ट्या धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध का कारित होना प्रकट करती है। विद्वान मजिस्ट्रेट ने अंतिम रिपोर्ट को खारिज करने में कोई अवैधता नहीं की है, क्योंकि आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बनता है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने भी आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज करने में कोई अवैधता नहीं की है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने **कनुमुक्कल कृष्णमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1965) 0 सीआर.एलजे 355, शिव नंदन पासवान बनाम बिहार राज्य, (1987) 1 एससीसी 288 और निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2021) 223 एआईसी 3** पर अवलम्ब लिया।

9. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और अभिलेख का परिशीलन करने के बाद, इस आवेदन में विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं:

(i) क्या, यह मानते हुए भी कि आवेदक ने चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय आपराधिक मामले के लंबित होने का खुलासा नहीं किया था, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी के आवश्यक तत्वों को प्रकट करती है, जिसमें छल, बेईमानी या कपटपूर्ण प्रलोभन, और उसके परिणामस्वरूप संपत्ति की सुपुर्दगी या क्षति की आवश्यकता शामिल है।

(ii) क्या आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना, परिस्थितियों की समग्रता में, प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसके लिए **राजीव थापर बनाम मदन लाल कपूर, (2013) 3 एससीसी 330** और हाल के निर्णयों जैसे **प्रदीप कुमार केसरवानी (उपरोक्त)** में प्रतिपादित सिद्धांतों को लागू करते हुए धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत है।

10. धारा 420 आईपीसी कोई स्वतंत्र अपराध नहीं है। यह धारा 415 आईपीसी में परिभाषित धोखाधड़ी के परिणामों से संबंधित है। धारा 420 बेईमानी से प्रलोभन के साथ धोखाधड़ी से संबंधित है जिसके कारण संपत्ति की सुपुर्दगी होती है या मूल्यवान प्रतिभूति में हस्तक्षेप होता है। वैधानिक अनुक्रम स्पष्ट है: धारा 420 इन शब्दों से शुरू होती है, "जो कोई धोखाधड़ी करता है और जिससे बेईमानी से प्रेरित करता है..." जब तक कि धारा 415 के तत्व पहले प्रकट न हों, धारा 420 को लागू नहीं किया जा सकता है।

11. धारा 415 अपराध को समझने के लिए एक परिभाषित संरचना को समाहित करती है। अभियोजन पक्ष को छल दिखाना होगा, जिसके बाद कानून द्वारा मान्यता प्राप्त प्रलोभन होना चाहिए, जो शुरुआत में ही आवश्यक आपराधिक आशय से समर्थित हो। इसके एक चरण में,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रलोभन "कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण" होना चाहिए और इसके परिणामस्वरूप संपत्ति की सुपुर्दगी या संपत्ति को रोके रखने की सहमति होनी चाहिए। दूसरे चरण में, प्रलोभन के कारण छले गए व्यक्ति को ऐसा कृत्य या लोप करना चाहिए जो वह अन्यथा नहीं करता, और उस कृत्य या लोप से शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को क्षति पहुँचना या पहुँचना संभावित होना चाहिए। यह कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जो हर चालाकी भरे कृत्य को अपराध घोषित करता हो; यह छल को केवल तभी अपराध मानता है जब वह कानून द्वारा चिन्हित विशेष परिणामों से जुड़ा हो।

12. संहिता स्वयं "बेईमानी से" और "कपटपूर्वक" के बीच अंतर को सुरक्षित रखती है। धारा 24 "बेईमानी से" को सदोष लाभ या सदोष हानि के संदर्भ में परिभाषित करती है। धारा 25 "कपटपूर्वक" को धोखा देने के आशय से कार्य करने के रूप में परिभाषित करती है। सर्वोच्च न्यायालय ने **डॉ. विमला बनाम दिल्ली प्रशासन, (1962) एससीसी ऑनलाइन 172** में स्पष्ट किया है कि "धोखाधड़ी" केवल छल तक सीमित नहीं है। इसके लिए छल के बाद छले गए व्यक्ति को क्षति पहुँचना आवश्यक है, और वह क्षति केवल आर्थिक होना आवश्यक नहीं है; इसमें शरीर, मन, ख्याति या अन्य कानूनी रूप से संज्ञेय क्षति शामिल हो सकती है। लेकिन क्षति की केवल कल्पना नहीं की जा सकती। इसे आरोपित तथ्यों और प्रतिपादित वैधानिक परिणामों पर आधारित होना चाहिए।

13. परिवादी के स्वयं के मामले में, "बेईमानी" का चरण शुरुआत में ही विफल हो जाता है। धारा 24 आईपीसी के तहत बेईमानी के लिए "सदोष लाभ" या "सदोष हानि" कारित करने का आशय होना आवश्यक है, जैसा कि धारा 23 आईपीसी में परिभाषित किया गया है, अर्थात् गैर-कानूनी साधनों द्वारा ऐसी संपत्ति का लाभ प्राप्त करना जिसके लिए प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है, या गैर-कानूनी साधनों द्वारा संपत्ति की ऐसी हानि जिसके लिए हानि उठाने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है।

14. आवेदक के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि वर्ष 2020 में चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय, उसने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि उसके विरुद्ध थाना स्वरूप नगर, जिला कानपुर नगर में अंतर्गत धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120बी आईपीसी के तहत वाद अपराध संख्या- 128 वर्ष 2018 दर्ज था। इसके पश्चात, दिनांक 29.06.2021 को

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चरित्र प्रमाण पत्र संख्या- 249/ए.आर.ए.-1/2020-21 जारी किया गया। इस मामले के तथ्यों के अनुसार, वर्तमान वाद अपराध संख्या- 200 वर्ष 2023 दर्ज कराने से पहले, विपक्षी संख्या- 2 ने दिनांक 21.04.2023 को जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर को एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि आवेदक ने चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वर्ष 2020 में आपके कार्यालय में आवेदन किया था और आवेदक ने, कपटपूर्ण तरीके से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के आशय से, वर्ष 2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 128 के तथ्य को जानबूझकर दबाकर जांच अधिकारी को धोखा दिया। उसने आगे आरोप लगाया कि आवेदक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा पहले ही समन किया जा चुका था। अतः उक्त चरित्र प्रमाण पत्र रद्द किया जाए।

15. इसके पश्चात, संबंधित प्राधिकारी ने विस्तृत और गहन जांच की। जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने आदेश दिनांक 12.09.2023 द्वारा उक्त परिवाद को निराधार और बिना किसी आधार के खारिज कर दिया।

16. जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के समक्ष दिनांक 21.04.2023 को उपरोक्त परिवाद दर्ज कराने के बाद, विपक्षी संख्या- 2 ने दिनांक 20.04.2023 को थाना कोतवाली, ईस्ट कमिश्नरेट, जिला कानपुर नगर में लगभग उन्हीं आरोपों के साथ धारा 198, 199, 205 और 420 आईपीसी के तहत वर्तमान वाद अपराध संख्या- 200 वर्ष 2023 दर्ज कराया, जो दिनांक 21.04.2023 की परिवाद में किए गए थे। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, विवेचक/जांच अधिकारी ने विपक्षी संख्या- 2 और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी एकत्र किए और पाया कि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है। तत्पश्चात, दिनांक 17.03.2024 को धारा 173(2) दं.प्र.सं. के तहत एक अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई। विपक्षी संख्या- 2 ने एक विरोध याचिका दायर की और विद्वान मजिस्ट्रेट ने उक्त रिपोर्ट को खारिज कर दिया और आवेदक को धारा 198, 199 और 420 आईपीसी के तहत समन कर लिया।

17. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक के विरुद्ध मुख्य आरोप यह है कि उसने आपराधिक मामले के दर्ज होने का खुलासा नहीं किया और चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया। विपक्षी संख्या- 2 ने यह आरोप नहीं लगाया है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक का खुद को सदोष लाभ पहुँचाने या विपक्षी संख्या- 2 को सदोष हानि पहुँचाने का कोई आशय था। इन आरोपों पर, आवेदक को गलत लाभ पहुँचाने या विपक्षी संख्या- 2 को गलत हानि पहुँचाने के किसी इरादे का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए, बेईमानी से की जाने वाली धोखाधड़ी का आधारभूत मानसिक तत्व अनुपस्थित है।

18. धारा 420 का आरोप दूसरे स्वतंत्र कारण से भी विफल हो जाता है। धारा 420 हर मिथ्या व्यपदेशन से आकर्षित नहीं होता है। यह केवल तभी आकर्षित होता है जहाँ धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप बेईमानी से ऐसा प्रलोभन दिया जाता है जिससे संपत्ति की सुपुर्दगी होती है या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को बनाने, बदलने या नष्ट करने का कृत्य होता है। कानून छल और संपत्ति-केंद्रित परिणाम के बीच एक स्पष्ट कारण-संबंधी संबंध पर जोर देता है। उस अर्थ में, धारा 420 पहली नज़र में जितनी दिखती है, उससे कहीं अधिक संकीर्ण है: यह धोखाधड़ी को केवल तभी दंडित करती है जब वह धारा में वर्णित कानूनी रूप से संज्ञेय परिणाम के रूप में समाप्त होती है।

19. यही कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा है कि धारा 420 के लिए धारा 415 के तहत धोखाधड़ी का होना अनिवार्य है, जिसमें बेईमानी से प्रलोभन के परिणामस्वरूप संपत्ति की सुपुर्दगी या मूल्यवान प्रतिभूति में हस्तक्षेप होना चाहिए, जैसा कि कानून में परिकल्पित है। यही सावधानी **मोहम्मद इब्राहिम बनाम बिहार राज्य, (2009) 6 एससीसी 751** जैसे निर्णयों में भी परिलक्षित होती है: जब तक कि परिवाद स्वयं वैधानिक तत्वों को प्रकट न करे, न्यायालय पक्षकारों को इस सिद्धांत पर विचारण के लिए नहीं भेजता कि गायब कड़ियाँ बाद में सामने आ सकती हैं।

20. यह बिंदु तब और स्पष्ट हो जाता है जब कोई देखता है कि सर्वोच्च न्यायालय इन सिद्धांतों को वास्तविक विवादों पर कैसे लागू करता है। **मरियम फसीहुद्दीन एवं अन्य बनाम राज्य व अन्य, एमएएनयू/एससी/0051/2024** के मामले में, इस धारणा पर आगे बढ़ते हुए भी कि माँ ने अपने बच्चे के पासपोर्ट आवेदन पर पिता के जाली हस्ताक्षर किए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे धारा 420 के तहत धोखाधड़ी मानने से इनकार कर दिया क्योंकि परिवादी को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सौंपने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था, और उसके प्रति कोई

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संपत्ति-संबंधी पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया था। छल, यदि मान भी लिया जाए, तो भी पर्याप्त नहीं था; महत्वपूर्ण उस वैधानिक परिणाम का अभाव था जो कृत्य को उसका आपराधिक स्वरूप प्रदान करता है।

21. **जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2025 आईएनएससी 1096** में, न्यायालय ने उस दावे पर विचार किया जिसमें अपनी शैक्षणिक संस्था चलाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक "झूठे एनओसी" का उपयोग किया गया था। न्यायालय ने पाया कि तथ्यों के आधार पर वास्तव में एनओसी की आवश्यकता ही नहीं थी, और इसलिए कथित मिथ्या व्यपदेशन ने प्राधिकारी को इस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जैसा कि वह अन्यथा नहीं करता। सामग्री प्रलोभन और परिणामी कानूनी पूर्वाग्रह की गायब कड़ी घातक साबित हुई। ये निर्णय इस बात की याद दिलाते हैं कि धारा 420 कोई इतना बड़ा जाल नहीं है जिसमें हर कथित झूठे दस्तावेज को फंसाया जा सके। छल को महत्वपूर्ण, कारण-युक्त और वैधानिक परिणाम उत्पन्न करने वाला होना चाहिए।

22. जब इन सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू किया जाता है, तो धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता है। आवेदक के विरुद्ध एकमात्र आरोप यह है कि उसने चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन करते समय अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले के बारे में खुलासा नहीं किया।

23. बेईमानी से प्रलोभन के तत्व को अनुपस्थित पाते हुए, समन आदेश धारा 415 के तहत वैकल्पिक मानसिक तत्व अर्थात् कथित "मन को ठेस/क्षति" का सहारा लेकर आरोप को बनाए रखने का प्रयास करता है। जैसा कि पहले देखा गया है, मन को होने वाली क्षति उस प्रकार की क्षति है जिसके माध्यम से कानून कपटपूर्ण आशय को मान्यता देता है - धोखाधड़ी का अर्थ क्षति के साथ छल का होना है। समस्या इस तर्क के साथ नहीं है कि मानसिक क्षति, सिद्धांत रूप में, प्रासंगिक हो सकती है। वास्तव में, डॉ. विमला (उपरोक्त) यह स्वीकार करती है कि "धोखाधड़ी" के उद्देश्यों के लिए "क्षति" आर्थिक नुकसान से आगे बढ़कर "मन को क्षति" तक विस्तृत हो सकती है। अड़चन केवल एक सामान्य परिवाद की भावना को उस वैधानिक क्षति में बदलने में है जो गायब आपराधिक दुराशय और परिणाम की पूर्ति के लिए आवश्यक है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



24. डॉ. विमला के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि कथित क्षति या लाभ को मामले के तथ्यों और आरोप की प्रकृति पर आधारित होना चाहिए। वहाँ, आरोप और साक्ष्य से न तो कोई लाभ और न ही बीमा कंपनी को कोई क्षति प्रकट हुई, जो किसी भी तरह से पूर्वग्रह से ग्रस्त नहीं थी और यदि सही तथ्यों का खुलासा किया गया होता तो भी वह अलग तरीके से कार्य नहीं करती, और इस प्रकार, दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया था। वर्तमान मामले में, आवेदक अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले के विवरण का खुलासा करने में विफल रहा। पहचानी गई एकमात्र 'मन को क्षति' यह है कि आवेदक ने जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के समक्ष अपने विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामले का खुलासा नहीं किया है। ऐसी अमूर्त अप्रसन्नता उस क्षति से बहुत दूर है, जिसे कानून शरीर, मन, ख्याति को नुकसान या किसी कानूनी अधिकार से वंचित करने के रूप में समझ सकता है। बेईमानीपूर्ण प्रलोभन या धोखाधड़ी से प्रेरित कानूनी रूप से संज्ञेय क्षति दोनों के अभाव में, धारा 415 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी का अपराध प्रकट नहीं होता है। एक बार जब धारा 415 के तहत धोखाधड़ी नहीं बनती है, तो धारा 420 के तहत आरोप स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।

25. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 (1)(ख) इस प्रकार है:

"195. लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए, लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंधित अपराधों के लिए अभियोजन।

(1) कोई भी न्यायालय-

(ख) (i) भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से किसी के भी अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अर्थात् धारा 193 से 196 (जिसमें ये दोनों धाराएं भी शामिल हैं), 199, 200, 205 से 211 (जिसमें ये दोनों धाराएं भी शामिल हैं) और 228 का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह किसी न्यायालय में की या उसके संबंध में किसी कार्यवाही में कारित किया गया है, या

(ii) उक्त संहिता की धारा 463 में वर्णित या धारा 471, धारा 475 या धारा 476 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, जब ऐसे अपराध के बारे में यह अभिकथित है कि वह

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किसी न्यायालय में की किसी कार्यवाही में पेश किए गए या साक्ष्य में दिए गए किसी दस्तावेज के संबंध में कारित किया गया है, या

(iii) उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी अपराध को कारित करने के किसी आपराधिक षड्यंत्र या उसे कारित करने के प्रयत्न या उसके दुष्प्रेरण का, संज्ञान

[केवल उस न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के, जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे, या किसी ऐसे अन्य न्यायालय के, जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही करेगा।]"

संहिता की धारा 195 के प्रावधान अनिवार्य हैं और इसका अनुपालन न करने से अभियोजन और अन्य सभी आनुषंगिक आदेश दूषित हो जाएंगे, जैसा कि 'सी. मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 2010 एससी 3718 के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

26. भारतीय दंड संहिता की धारा 198 और 199 की अंतर्वस्तु और उसके आवश्यक तत्व नीचे पुनःउद्धृत किए जा रहे हैं:

198. ऐसे प्रमाण पत्र का असली के रूप में उपयोग करना जिसका मिथ्या होना ज्ञात है-
जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को, जिसके बारे में वह जानता है कि वह किसी तात्विक बात में मिथ्या है, भ्रष्टतापूर्वक असली प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

199. किसी ऐसी घोषणा में मिथ्या कथन करना जो विधि द्वारा साक्ष्य के रूप में ली जाने योग्य है-

जो कोई किसी ऐसी घोषणा में, जिसे करने या जिस पर हस्ताक्षर करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो, और जिसे कोई न्यायालय या कोई लोक सेवक या अन्य व्यक्ति किसी तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध या प्राधिकृत हो, ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, और जो उस उद्देश्य से

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संगत किसी तात्विक बात के संबंध में हो जिसके लिए वह घोषणा की गई है या उपयोग में लाई गई है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो।

27. भारतीय दंड संहिता की धारा 198 की परिभाषा के अनुसार, जो कोई किसी ऐसे प्रमाण पत्र को भ्रष्टापूर्वक असली प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग में लाएगा या उपयोग में लाने का प्रयत्न करेगा, जिसके बारे में वह जानता है कि वह किसी तात्विक बात में मिथ्या है, वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने मिथ्या साक्ष्य दिया हो। वर्तमान मामले के अनुसार, चरित्र प्रमाण पत्र आवेदक के पक्ष में जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा उचित जांच के बाद जारी किया गया था। उक्त प्रमाण पत्र एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था। उक्त प्रमाण पत्र कोई जाली या कूट रचित दस्तावेज नहीं है और न ही किसी प्राधिकारी द्वारा इसे मिथ्या प्रमाण पत्र घोषित किया गया है। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 198 में उल्लिखित तत्व पूरे नहीं होते हैं।

28. जहाँ तक आवेदक को धारा 199 आईपीसी के तहत समन करने का संबंध है, कोई भी न्यायालय धारा 199 आईपीसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है, सिवाय उस न्यायालय के या न्यायालय के ऐसे अधिकारी के जिसे वह न्यायालय इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत करे, या किसी ऐसे अन्य न्यायालय के जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, लिखित परिवाद पर ही ले सकता है। यहाँ, चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर को किया गया था और जिला मजिस्ट्रेट ने उचित जांच के बाद उक्त चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया था। परिवाद जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकार प्राप्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए, मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 199 आईपीसी के तहत पारित समन आदेश कानून की दृष्टि में त्रुटिपूर्ण है।

29. मैंने विपक्षी संख्या- 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल किए गए न्यायिक दृष्टांतों का परिशीलन किया है, परंतु इन दृष्टांतों में वर्णित तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न हैं और इन दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों का कोई लाभ विपक्षी संख्या- 2 को नहीं दिया जा सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



30. शेष प्रश्न यह है कि क्या इन कमियों के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को अभी भी एक पूर्ण आपराधिक विचारण की कठोरता से गुजरना चाहिए, इस आधार पर कि इन सभी मुद्दों को आरोप तय करने के चरण या अंतिम निर्णय के समय परीक्षण के लिए छोड़ा जा सकता है। इससे संबंधित शासी सिद्धांत अब सुस्थापित हैं।

31. **भजन लाल** (उपरोक्त) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने उन उदाहरणात्मक श्रेणियों को निर्धारित किया था जिनमें उच्च न्यायालय कार्यवाहियों को निरस्त करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ऐसी ही एक श्रेणी वह है जहाँ अकाट्य आरोपों और एकत्र की गई सामग्री से किसी अपराध का कारित होना प्रकट नहीं होता है। दूसरी श्रेणी, जो यहाँ विशेष रूप से प्रासंगिक है, वह है जहाँ आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित हो या दुर्भावनापूर्वक किसी गुप्त उद्देश्य से, प्रतिशोध लेने के लिए या अभियुक्त को निजी या व्यक्तिगत रंजिश के कारण तंग करने के लिए संस्थित की गई हो।

32. **राजीव थापर** (उपरोक्त) के मामले में, न्यायालय ने बचाव पक्ष की ऐसी सामग्री के आधार पर, जो इतनी उत्कृष्ट गुणवत्ता की हो कि कोई भी समझदार व्यक्ति उसकी उपेक्षा न कर सके, निरस्तीकरण के लिए चार चरणों वाली जांच की रूपरेखा तैयार करके दृष्टिकोण को और परिष्कृत किया। यह ढांचा, जिसका पालन **प्रदीप कुमार केसरवानी** सहित बाद के निर्णयों में किया गया है, न्यायालय से यह पूछने की अपेक्षा करता है: क्या अभियुक्त द्वारा भरोसा की गई सामग्री ठोस और अकाट्य है; क्या यह परिवाद में किए गए तथ्यात्मक दावों को सीधे झुठलाती है; क्या यह अखण्डनीय रहती है; और क्या ऐसी सामग्री के आलोक में कार्यवाहियों को जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

33. इन कारणों से और चर्चा को धारा 198, 199 और 420 आईपीसी के तहत मुख्य अपराधों तक सीमित रखते हुए, यह न्यायालय संतुष्ट है कि यदि परिवादी के आरोपों को उनके सर्वोपरि स्तर पर भी लिया जाए, तो भी **डॉ. विमला, मरियम फसीहुद्दीन** (उपरोक्त) और **जुपल्ली लक्ष्मीकांत रेड्डी** (उपरोक्त) में समझाए गए धोखाधड़ी और कूटरचना के आवश्यक तत्व प्रकट नहीं होते हैं। यहाँ छल से जुड़ी संपत्ति की कोई वंचना या हानि नहीं हुई है, मूल्यवान प्रतिभूति

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में कोई कानूनी रूप से संज्ञेय हस्तक्षेप नहीं हुआ है, और न ही किसी झूठे दस्तावेज के निर्माता की पहचान हुई है जिसे आवश्यक आपराधिक दुराशय से जोड़ा जा सके।

34. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का अस्तित्व आपराधिक प्रक्रिया को वहां इस्तेमाल होने से रोकने के लिए है जहां अभियोजन पक्ष के पास, अपने स्वयं के प्रदर्शन पर भी, दोषसिद्धि तक पहुंचने की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। यह ऐसा ही एक मामला है। कार्यवाहियों को जारी रखने की अनुमति देने से आपराधिक कानून की संपुष्टि नहीं होगी; यह गंभीर दंडात्मक आरोपों की आड़ में व्यवसाय से जुड़े एक व्यक्तिगत विवाद को केवल लंबा खींचेगा।

35. इसलिए, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है। विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1, कानपुर नगर द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या- 732 वर्ष 2024, राजीव तलरेजा बनाम रोमेन्द्र मेहता में पारित समन आदेश दिनांक 22.08.2024 और विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या- 18, कानपुर नगर द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण संख्या- 593 वर्ष 2024, रोमेन्द्र मेहता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांक 28.07.2025 को निरस्त किया जाता है। प्रकीर्ण वाद संख्या- 732 वर्ष 2024, राजीव तलरेजा बनाम रोमेन्द्र मेहता से उद्भूत संपूर्ण कार्यवाहियों को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति चवन प्रकाश)

04 जून, 2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।